(ख) विचार गोष्ठी द्वारा नये बाजार नगरों की स्थापना का कोई सुझाव नहीं दिया गया है, अत: प्रश्न ही नहीं होता ।

Setting up of an Agency for Exploration of Export Potential of Indian Fruits

1773. SHRI BALATHANDAYUTHAM :
SHRI P. GANGADEB :
SHRI S. A. MURUGANANTHAM:

Will the Minister of AGRICULTURE be pleased to state :

(a) whether Government are going to set up a co-ordinated agency for carrying out research, development and to explore the export potential of Indian fruits ; and

(b) if so, the main features of the scheme ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF AGRICULTURE (SHRI ANNASAHEB P. SHINDE) : (a) Government have no such proposal under consideration.

(b) Does not arise.

ऋण का शीघ्र भुगतान करने हेतु सरकारी समितियों के लिए आदर्श कानून

1774. **श्री रामावतार शास्त्री** : क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विभिन्न राज्यों में सहकारी समितियों के सदस्यों को समय पर शीघ्र ऋण प्राप्त करने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है ; और

(ख) यदि हा, तो क्या सरकार का विचार समस्त राज्यों के लिए कोई आदर्श कानून बनाने का है ?

कृषि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री जगन्नाथ पहाड़िया) : (क) और (ख). भारत सरकार ने 1956 में एक समिति नियुक्त की, जिसने समग्र देश के लिए सामान्यत: उपयुक्त एक सरल वैधानिक उपाय की सिफारिश करनी थी, जिससे कि इस आंदोलन की समन्वित प्रगति को सुकर बनाया जा सके । इस समिति ने एक आदर्श सहकारी समिति विधेयक, आदर्श सहकारी समिति नियमों और कुछ महत्वपूर्ण किस्मों की सहकारी समितियों के लिए आदर्श उप-विधियों के एक सेट के प्रारूप तैयार किए । इस समिति की रिपोर्ट राज्य सरकारों/केन्द्र शासित क्षेत्रों को आवश्यक कार्यवाही के लिए भेजी गई थी ।

राष्ट्रीय विकास परिषद ने भी 1958 में हुई अपनी बैठक में सहकारी कानून तथा प्रक्रिया को सरल बनाने के प्रश्न पर विचार किया, ताकि सहकारी आंदोलन के ठोस तथा द्रुत विकास को सुकर बनाया जा सके । ये सुझाव राज्य सरकारों को वर्ष 1959 में आवश्यक कार्यवाही के लिए सूचित किए गए थे । भारत सरकार भी सहकारी विधान को आर्थिक विकास के लिए आमतौर पर और ग्रामीण विकास के लिए विशेष तौर पर कारगर माध्यम बनाने के प्रश्न पर बारंबार विचार करती रही है और राज्य सरकारों को अपने कानूनों में उपयुक्त संशोधन करने की सिफारिश करती रही है । भारत सरकार की कुछ सिफारिशों से ग्रामीण समाज के आर्थिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों को सहकारी ऋण सुविधापूर्वक सुलभ करने की दिशा में स्पष्ट रूप से प्रभाव पड़ा है ।

तथापि सहकारी विधान के एक आदर्श ढांचे के रूप में सहकारी विधि समिति की सिफारिशें और आदर्श विधि आज भी लागू है ।

Crash Employment Programme in Orissa

1775. SHRI P. K. DEO : Will the Minister of AGRICULTURE be pleased to state :

(a) the District-wise break up of the crash programme for removal of rural unemployment in the State of Orissa ; and

(b) the number of persons who have been provided with employment by this programme ?